शनिवार, 18 अप्रैल, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

IPL के असली चेज मास्टर हैं श्रेयस अय्यर

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

कार्तिक आर्यन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा का आदेश दिया

Page-05

ईरान-अमेरिका सीजफायर की उम्मीदों से बाजार में जबरदस्त तेजी लौटी। सेंसेक्स 77,500 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने नया रिकॉर्ड छू लिया। गिरते कच्चे तेल और बेहतर ग्लोबल संकेतों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश!

दोहरी नागरिकता के आरोपों की जांच के निर्देश

- **हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता आरोपों पर एफआईआर दर्ज कर जांच के निर्देश दिए।**
- **सुलतानपुर कोर्ट ने मानहानि केस में देरी पर सख्ती दिखाते हुए वादी पक्ष को चेतावनी दी।**

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों की गंभीर जांच जरूरी है। अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह खुद जांच करे या इसे किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपे।यह मामला भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर सामने आया, जिसमें लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी। निचली अदालत ने पहले एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाया है।इधर, सुलतानपुर की विशेष अदालत में चल रहे मानहानि मामले में भी सुनवाई के दौरान कड़ा रुख देखने को मिला। अदालत ने वादी पक्ष को बार-बार स्थगन लेने पर फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि धारा 311 के तहत दाखिल अर्जी पर बहस होनी थी, लेकिन वादी पक्ष ने फिर से समय मांगा।अदालत ने चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई पर वादी पक्ष उपस्थित नहीं होता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इससे पहले 28 मार्च को वादी पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना लेने की भी मांग की थी, जिस पर अदालत में बहस जारी है।कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद मामला और गंभीर हो सकता है और जांच एजेंसियों की भूमिका अहम हो जाएगी। आने वाले दिनों में इस मामले में कई नए कानूनी और राजनीतिक पहलू सामने आ सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल बढ़ने की संभावना है।

विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग: वैश्विक मुद्दों पर भारत का संतुलित और सख्त रुख

भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भारत की स्पष्ट नीति रखी। ब्रीफिंग में पश्चिम एशिया की स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा, पड़ोसी देशों से संबंध, प्रत्यर्पण और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई।इजराइल-लेबनान संघर्षविराम को लेकर भारत ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं हमास से जुड़े मुद्दे पर कहा गया कि भारत निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत ही कार्रवाई करता है।ऊर्जा सहयोग पर भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देशों—बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरीशस और सेशेल्स—के साथ सहयोग जारी रखे हुए है।बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मामले पर बताया गया कि भारत को मिला अनुरोध कानूनी प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है और इस पर रचनात्मक संवाद जारी रहेगा।ईरान संकट के दौरान भारतीय नागरिकों की वापसी पर जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि अब तक 2361 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है, जिनमें 1041 छात्र शामिल हैं। साथ ही तीन विदेशी नागरिकों को भी मदद दी गई।आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने कहा कि वह ब्रिटेन के साथ लगातार संपर्क में है और सभी भगोड़ों को कानून के दायरे में लाना सरकार की प्राथमिकता है।जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर पाकिस्तान की टिप्पणियों को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए दोहराया कि ये दोनों क्षेत्र देश के अभिन्न अंग हैं और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है।

'यह आरक्षण नहीं, चुनावी नक्शा बदलने की साजिश'

पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच जहां एक ओर अस्थायी शांति देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच 32 घंटे के संघर्षविराम ने दुनिया को थोड़ी राहत दी है। यह युद्धविराम शनिवार शाम से रविवार रात तक प्रभावी रहेगा। क्रेमलिन ने अपने रक्षा मंत्री के माध्यम से सेना को सभी दिशाओं में सैन्य कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं, हालांकि किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए सेना को तैयार रहने को भी कहा गया है। ऐसे में यह शांति बेहद नाजुक मानी जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इसे मानवीय जरूरत बताते हुए कहा कि लोग शांति से ईस्टर मना सकें, लेकिन उन्होंने स्थायी समाधान को लेकर संदेह भी जताया। इससे पहले भी ऐसे संघर्षविराम विफल हो चुके हैं और दोनों देशों के बीच भरोसा काफी कमजोर हो चुका है। कुल मिलाकर, यह संघर्षविराम अस्थायी राहत जरूर देता है, लेकिन स्थायी शांति की राह अब भी कठिन और अनिश्चित बनी हुई है।

यूपी में बड़ा सियासी धमाका तय!

संगठन से लेकर मंत्रिमंडल तक महा फेरबदल

काफी समय से चल रही चर्चाओं और विचार-विमर्श के बाद अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में बड़े फेरबदल के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठकें कीं, जिनमें संगठन और सरकार दोनों स्तर पर बदलाव को लेकर मंथन हुआ।दिसंबर में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही पंकज चौधरी पर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। लंबे समय से पदों पर बैठे नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका देने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, ताकि बदलते राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से पार्टी खुद को ढाल सके।सूत्रों के मुताबिक भाजपा ओबीसी और दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत करने पर खास फोकस कर रही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में इन वर्गों का कुछ समर्थन सपा-कांग्रेस की ओर जाता दिखा था। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी को दूर करना भी पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है।संगठनात्मक बदलाव के साथ-साथ सबसे ज्यादा चर्चा राज्य मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर है। माना जा रहा है कि पांच से छह नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन को देखते हुए बड़े स्तर पर बदलाव की भी योजना है, हालांकि व्यापक फेरबदल में अभी कुछ समय लग सकता है।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2 - 3)	फुल पेज (कवर 4- अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

चारधाम यात्रा 2026 का महाआगाज़!

18 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड में 23 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। प्रशासनिक निरीक्षण और लगातार समीक्षा बैठकों के बाद अधिकारियों का कहना है कि इस बार यात्रा को लेकर देश-विदेश के श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक अब तक करीब 18 लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री के लिए 3.7 लाख से अधिक, गंगोत्री के लिए करीब 3.16 लाख, केदारनाथ के लिए 6.19 लाख, बद्रीनाथ के लिए 5.27 लाख और हेमकुंड साहिब के लिए 17 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल मिलाकर यह संख्या लगभग 17.87 लाख तक पहुंच चुकी है।सरकार ने यात्रा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत से बचने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर ली हैं। मंत्री ने साफ किया कि खाना पकाने की गैस, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।उन्होंने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा पूरी तरह सामान्य तरीके से संचालित होगी और सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड आकर अपनी धार्मिक आस्था पूरी करने का आमंत्रण दिया गया है।इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद केदारनाथ मार्ग सहित कई अहम स्थानों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

हॉर्मुज जलडमरूमध्य पर वैश्विक संकट

फ्रांस-ब्रिटेन की पहल, अमेरिका बैठक से बाहर

इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।इस संकट को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बुलाया है।इस बैठक में कई देशों की भागीदारी है, लेकिन अमेरिका को इससे दूर रखा गया है ताकि निष्पक्ष समाधान निकाला जा सके।दोनों देशों ने जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर पहल तेज कर दी है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते तेहरान द्वारा पूरी तरह ब्लॉकेड किए गए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन बुला लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर शुक्रवार को दर्जनों देशों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ताकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की योजना को आगे बढ़ाया जा सके। यह महत्वपूर्ण तेल मार्ग अमेरिका-इज़रायल और ईरान युद्ध के कारण बंद हो गया है। पेरिस में हो रही यह बैठक उन देशों के प्रयासों का हिस्सा है, जो इस संघर्ष में शामिल नहीं हैं और न ही इसे शुरू किया था। होर्मुज की नाकाबंदी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इस संकरे जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। इस रास्ते से दुनिया के कुल तेल के पांचवें हिस्से की सप्लाई होती थी। हॉर्मुज जलडमरूमध्य समुद्री नौवहन स्वतंत्रता पहल" नाम से जानी जा रही इस योजना की तैयारी में अमेरिका शामिल नहीं है।फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने शुक्रवार को हो रहे इस सम्मेलन से पहले एक्स पर लिखा कि होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए मिशन "सख्ती से रक्षात्मक" होगा। यह केवल गैर-युद्धरत देशों द्वारा संचालित किया जाएगा और इसे "सुरक्षा स्थितियां अनुमति देने पर" तैनात किया जाएगा। मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने ईरान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व किया है। स्टार्मर ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह "दुनिया की अर्थव्यवस्था को फिरौती" में रखे हुए है। ट्रम्प द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर जवाबी नाकेबंदी की घोषणा से आर्थिक खतरा और बढ़ गया है। ब्रिटिश पीएम स्टार्मर ने बैठक से पहले कहा, "जलडमरूमध्य को बिना शर्त और तुरंत फिर से खोलना एक वैश्विक जिम्मेदारी है। हमें कार्रवाई करनी होगी, ताकि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार फिर से स्वतंत्र रूप से बह सके।" फ्रांस और ब्रिटेन ने सैन्य योजना की बैठकें भी आयोजित की हैं, जो यूक्रेन युद्ध में संभावित युद्धविराम के बाद सुरक्षा प्रदान करने के लिए बने "इच्छुक गठबंधन" की याद दिलाता है। फ्रांसीसी सैन्य प्रवक्ता कर्नल गिलॉम वर्नेट ने गुरुवार को कहा कि मिशन अभी भी "निर्माणाधीन" है। मैक्रों के कार्यालय ने कहा कि भाग लेने वाले देश "अपनी क्षमता के अनुसार" योगदान देंगे। स्थायी युद्धविराम के बाद सुरक्षा स्थिति के आधार पर जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने के विकल्प तय किए जाएंगे। एक फ्रांसीसी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाज संचालक यह सुनिश्चित कर सकें कि अगर उनका जहाज जलडमरूमध्य से गुजरेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा।

फिलीपींस में 2026 की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

फिलीपींस में इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 संदिग्ध मुस्लिम उग्रवादियों को मार गिराया। यह कार्रवाई शुक्रवार को देश के दक्षिणी हिस्से में हुई, जहां लंबे समय से अलगाववादी हिंसा होती रही है। अधिकारियों के मुताबिक, यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना और पुलिस एक गांव में एक उग्रवादी कमांडर को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। तभी 'दौलह इस्लामिया-माउते' नाम के समूह से जुड़े संदिग्ध उग्रवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद करीब एक घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी चली। इस ऑपरेशन में कमांडर अमेरोल मंगोरांका समेत कुल 10 उग्रवादी मारे गए, जिनमें चार महिलाएं भी शामिल थीं। राहत की बात यह रही कि इस मुठभेड़ में किसी भी सरकारी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा। सेना के अधिकारियों का कहना है कि मंगोरांका और उसके साथी पहले भी कई हमलों में शामिल रहे थे। जनवरी में हुए एक घात लगाकर हमले में चार सैनिकों की मौत के पीछे भी इसी समूह का हाथ बताया गया था। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से चार राइफल, एक पिस्टल, एक ग्रेनेड और बम बनाने का सामान बरामद किया। इस दौरान एक शिशु भी घटनास्थल पर मिला, जिसे तुरंत इलाज के लिए भेजा गया। हालांकि, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। फिलीपींस के दक्षिणी इलाके में दशकों से मुस्लिअलगाववादी आंदोलन म चलता रहा है। हालांकि, साल 2014 में मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट शांति समझौता के बाद हालात काफी हद तक सुधर गए थे। इस समझौते के तहत बड़े उग्रवादी समूह ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता अपनाया था। लेकिन कुछ छोटे गुट इस समझौते में शामिल नहीं हुए और अब भी समय-समय पर हमले करते रहते हैं।

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही जमानत बढ़ाने की मांग से किया इनकार

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही। कोर्ट ने खेड़ा की ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम की अदालत में याचिका दायर की जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले आदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित नही होगा। खेड़ा को आज दोपहर के बाद गुवाहाटी हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल करने का दिया आदेश। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा द्वारा हाईकोर्ट में गलत दस्तावेज लगाने पर कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फर्जी दस्तावेज को लेकर की गई हमारी टिप्पणी से गुवाहाटी हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई प्रभावित नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। खेड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि मामले में एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया गया है। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा को मिली ट्रांजिट बेल की अवधि खत्म हो रही है। उन्होंने कहा इस देश में अनुच्छेद 21 है। तेलंगाना याचिका जल्दबाजी में दायर की गई थी, बहस के दौरान इस ओर ध्यान दिलाया गया और सही दस्तावेज़ दाखिल किया गया। मेरी पत्नी तेलंगाना में विधायक पद की उम्मीदवार हैं, उनका हलफनामा भी उसी दिन दाखिल किया गया था। इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। निज़ामुद्दीन में 100 पुलिसकर्मी भेजे गए हैं, इस देश में अनुच्छेद 21 लागू है। वह आपको यह नहीं बताता कि सही दस्तावेज़ दाखिल किया गया है। यह सब पक्षपात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप असम में दाखिल करें। सिंघवी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा... मुझे आज या कल दाखिल करने की अनुमति दें,अदालत बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल का आदेश पारित हुआ था।आपने यह अर्जी कल दाखिल की। आपने इसे हाईकोर्ट में क्यों नहीं दाखिल किया? आप आज ही दाखिल करें। इस पर सुनवाई होगी।

अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की महत्वपूर्ण शांति वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी युद्ध को समाप्त करना है। इस युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा की आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। पिछले हफ्ते हुई पहली सीधी बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई थी। हालांकि, दोनों पक्ष अभी दो हफ्ते के अस्थायी युद्धविराम का पालन कर रहे हैं। यह युद्धविराम 22 अप्रैल को समाप्त होगा। पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाकर दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। अधिकारिक ने सूत्रों ने शुक्रवार को कहा, दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल पर वापस लाने के लिए तेजी से डिप्लोमैटिक काम हुआ। इस शांति प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काफी सक्रिय हैं। पर्दे के पीछे काम करने के बाद, प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की के नेताओं से बातचीत की है। वहीं, फील्ड मार्शल मुनीर ने तेहरान में ईरान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के साथ मुलाकात की। हालांकि, बातचीत के नतीजे के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इस्लामाबाद के अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा के लिहाज से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारी इंतजाम किए जा रहे हैं। दूसरे प्रांतों से हजारों पुलिस और अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया है। पहले दौर की बातचीत में 10,000 से ज्यादा जवान तैनात रहे थे। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अगले हफ्ते यातायात पर कड़ी पाबंदियां रहेंगी। जरूरत पड़ने पर स्कूल और बाजार भी बंद किए जा सकते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर असहमति की वजह से पिछला समझौता नहीं हो पाया। दूसरी तरफ, ईरान के प्रतिनिधि मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि उनकी टीम ने आगे की पहल की, लेकिन दूसरी तरफ की पार्टी इस बातचीत के दौर में ईरानी डेलीगेशन का भरोसा जीतने में नाकाम रही।

CAPF की पहली शीर्ष कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' की एक अहम कॉन्फ्रेंस के आयोजन की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। खुफिया ब्यूरो 'आईबी' को इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पहली बार हो रहा है, जब आंतरिक सुरक्षा को लेकर सीएपीएफ की इस तरह की कॉन्फ्रेंस होगी। अभी तक डीजी/आईजी का सालाना सम्मेलन होता रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हिस्सा लेते हैं। सभी केंद्रीय बलों में इस खास सम्मेलन को लेकर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कुछ रैंकों से सम्मेलन के एजेंडे को लेकर सुझाव देने के लिए कहा गया है। बता दें कि पिछले दिनों संसद में 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026', पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। देश में अब सीएपीएफ का नया कानून लागू हो गया है। सीएपीएफ के पूर्व कैडर अफसर इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व कैडर अफसर, नए कानून की खिलाफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कैडर अफसरों की पदोन्नति के अवसर खत्म होंगे। वे पदोन्नति में पिछड़ते चले जाएंगे। गृह मंत्रालय को इस मामले में असीमित शक्तियां मिल जाएंगी। 'अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन' के तत्वावधान में पूर्व कैडर अफसर और उनके परिजन छह मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले जब डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें सभी केंद्रीय बलों के डीजी मौजूद रहते हैं। केवल सीएपीएफ के शीर्ष अफसरों की कॉन्फ्रेंस, पहली बार आयोजित की जा रही है। जिस तरह से डीजी आईजी सम्मेलन, आईबी द्वारा आयोजित किया जाता है, उसी तरह सीएपीएफ सम्मेलन भी खुफिया ब्यूरो ही आयोजित कर रह है। हालांकि अभी सम्मेलन की तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि यह सम्मेलन जल्द ही आयोजित होगा। इस सम्मेलन का मकसद, सीएपीएफ के शीर्ष नेतृत्व को विभिन्न तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफार्म मुहैया कराना है। इसके जरिए आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ काम किया जाएगा।

संपादक की कलम से

"महिला आरक्षण—नारी शक्ति का विस्तार या राजनीति का नया अखाड़ा?"

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चल रही चर्चा ने देश की राजनीति को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। वर्षों से लंबित यह मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर दिखाई दे रहा है। सरकार इसे "नारी शक्ति का अधिकार" बता रही है, वहीं विपक्ष इसके क्रियान्वयन के तरीके और समय पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि इस बहस को केवल राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि सामाजिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए।महिला आरक्षण का उद्देश्य स्पष्ट है—राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सशक्त बनाना। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां आधी आबादी महिलाएं हैं, वहां संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इस लिहाज से यह कदम ऐतिहासिक और स्वागत योग्य कहा जा सकता है।हालांकि, इस मुद्दे के साथ परिसीमन (Delimitation) और जनगणना को जोड़ने से कई नए सवाल भी खड़े हो गए हैं। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में यह आशंका जताई जा रही है कि नई व्यवस्था से उनके प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। सरकार ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए भरोसा दिलाया है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन यह भरोसा जमीन पर कितना साकार होता है, यह आने वाला समय बताएगा।दूसरी ओर, विपक्ष का यह तर्क भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने के बजाय भविष्य की जनगणना और परिसीमन से जोड़ना इसे टालने की रणनीति हो सकती है। साथ ही, ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग भी इस बहस को और जटिल बनाती है।अंततः, महिला आरक्षण केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम है। इसे राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर उठकर लागू किया जाना चाहिए। यदि सभी दल ईमानदारी से इस दिशा में सहयोग करें, तो यह कदम भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी और मजबूत बना सकता है। वरना, यह भी एक और अधूरा वादा बनकर रह जाएगा, जिसकी कीमत देश की आधी आबादी को चुकानी पड़ेगी।

महिला आरक्षण पर संसद में घमासान

मोदी का भरोसा, अमित शाह ने परिसीमन पर दी सफाई

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति का अधिकार बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिसीमन में किसी भी राज्य, खासकर दक्षिण भारत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से बताया कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों की लोकसभा सीटें और प्रतिनिधित्व दोनों बढ़ेंगे।साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जाति जनगणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीनों बिल पेश हो गए हैं और इस पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण नारी शक्ति का हक है और जो भी बिल का विरोध करेगा वो चुनाव हारेगा, आरक्षण का विरोध करने वालों को महिलाएं माफ नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विपक्षी दलों को ये भरोसा भी दिया कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोकसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने परिसीमन के मुद्दे पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के हर राज्य को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोलते हुए कहा, "एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि यह जो तीन विधेयक हैं: संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव का कानून, यह आने से लोकसभा में दक्षिण की क्षमता कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा।" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोलते हुए कहा, "आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, अब की स्थिति में उनका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60% है इसमें भी लगभग 50% वृद्धि होगी और सीटें हो जाएंगी 38... तेलंगाना में अभी 17 सीटें हैं और उनकी शक्ति 3.13% है, वृद्धि के बाद 26 सीटें हो जाएगी और 3.18% उनकी क्षमता हो जाएगी। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। अभी 39 सांसद तमिलनाडु से चुनकर आते हैं और उनकी क्षमता 7.18% है, वृद्धि के बाद सांसद 59 हो जाएंगे और नए सदन में क्षमता 7.23% हो जाएगी। तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं होगा। कर्नाटक में वर्तमान में 28 लोकसभा सीटें हैं और सदन में उनकी हिस्सेदारी 5.15 प्रतिशत है। परिसीमन के बाद कर्नाटक की लोकसभा सीटें बढ़कर 42 हो जाएंगी। इसके साथ ही लोकसभा में उनकी हिस्सेदारी भी 5.14 प्रतिशत हो जाएगी। कर्नाटक को कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही केरल केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जो कि सदन में 3.68 प्रतिशत है। परिसीमन विधेयक पारित होने के बाद सांसदों की संख्या 30 हो जाएगी और नए सदन में उनका प्रतिशत 3.67 प्रतिशत होगा। कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है, अभी 543 सीटों में उनके 129 सांसद बैठते हैं, 23.76% दक्षिण सांसदों की शक्ति यहां है, 50% वृद्धि के बाद 129 की जगह 195 सांसद दक्षिण के होंगे और उनकी शक्ति 23.97% होगी।" केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोलते हुए कहा, "एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें जाति का जिक्र नहीं है। जनगणना दो हिस्सों में होती है, पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है, उसके बाद उन मकानों में रहने वाले लोगों को इंगित किया जाता है। इन्होंने(विपक्ष) कहा कि जाति जनगणना सरकार नहीं कराना चाहती। सरकार की कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है और अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है।"केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर लोकसभा में बोलते हुए कहा, "डीलिमिटेशन कमीशन का ज़िक्र था कि आप डीलिमिटेशन कमीशन में अपने लोगों को बैठा देंगे और वे ये-वो करेंगे। मैं प्रियंका गांधी को बताना चाहता हूं कि हमने डीलिमिटेशन कमीशन में कोई बदलाव नहीं किया है। हमने आपके डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को दोहराया है। अगर आपने इसमें हेरफेर किया होगा, तो मैं कह सकता हूं कि हम ऐसा नहीं करेंगे।"

महिला आरक्षण पर प्रियंका गांधी का पलटवार: 'आधा सच बता रही है भाजपा, कांग्रेस हमेशा से समर्थन में

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा में महिला आरक्षण पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिलाओं के संरक्षण और आरक्षण के पक्ष में मजबूती से खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री की आज की टिप्पणियों से ऐसा लगा जैसे भाजपा महिला आरक्षण की प्रणेता और सबसे बड़ी समर्थक रही है। उनके पूरे भाषण का विषय यही था, भले ही उन्होंने यह दावा किया कि वह इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहते... साल 2023 में राहुल गांधी के पत्र को पढ़ने के कुछ वर्षों बाद, अंततः जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2023 में सर्वसम्मति से इस अधिनियम को पारित किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुरूप इसका पूरा समर्थन किया।" कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "आज प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र तो किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने केवल आधा सच बोला। उन्होंने सदन को बताया कि विरोध हुआ था, लेकिन स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वास्तव में विरोध किसने किया था। उन्होंने कहा कि विरोध हुआ, पर यह नहीं बताया कि किसके द्वारा किया गया। हकीकत तो यह है कि वह आप (भाजपा) ही थे, जिन्होंने इसका विरोध किया था। इसके कुछ वर्षों बाद, पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने संसद में इस कानून को पारित किया और इसे लागू किया।" प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "यह एक ऐसा विषय है जो हर महिला के दिल में एक विशेष स्थान रखता है, इसलिए इस पर बोलने का मौका मिलने के लिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देती हूं। मैं संक्षेप में इस मुद्दे की पृष्ठभूमि समझाना चाहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिक्र किया था कि इसे किसने रोका, कैसे रोका गया और इस निर्णय में 30 साल की देरी क्यों हुई। सत्ता पक्ष के मेरे साथियों को शायद यह पसंद न आए, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि इसकी नींव उस नेहरू ने नहीं रखी थी जिनका आप अक्सर जिक्र करते हैं। ये वो नेहरू नहीं हैं जिन्हें लेकर आप संकोच करते हैं। यह उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की थी और उसे कांग्रेस कार्यसमिति को सौंपा था। वह उस समिति के अध्यक्ष थे और इसमें उन्होंने 19 मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया था।"

बंगाल चुनाव 2026: हर चौथा उम्मीदवार आपराधिक केस में घिरा

हर पांचवां करोड़पति—ADR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव मैदान में उतरे लगभग हर 4 में से एक उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि हर पांचवां उम्मीदवार करोड़पति है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 1475 उम्मीदवारों में से 345 (23 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की जानकारी दी है। इनमें से 294 (20 प्रतिशत) उम्मीदवार गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 19 उम्मीदवारों पर हत्या से जुड़े मामले दर्ज हैं, जबकि 105 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास के आरोप हैं। इसके अलावा 98 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं, जिनमें 6 उम्मीदवारों पर दुष्कर्म के आरोप भी शामिल हैं। अगर प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें, तो सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार बीजेपी के हैं। पार्टी के 152 में से 106 उम्मीदवार (70 प्रतिशत) ने ऐसे मामलों की जानकारी दी है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 63 उम्मीदवार (43 प्रतिशत), CPM के 43 उम्मीदवार (44 प्रतिशत) और कांग्रेस के 39 उम्मीदवार (26 प्रतिशत) इस सूची में शामिल हैं। गंभीर आपराधिक मामलों में भी यही रुझान देखा गया। बीजेपी के 63 प्रतिशत, तृणमूल कांग्रेस के 32 प्रतिशत, CPM के 37 प्रतिशत और कांग्रेस के 22 प्रतिशत उम्मीदवारों पर गंभीर आरोप हैं। रिपोर्ट में 66 विधानसभा सीटों (करीब 43 प्रतिशत) को 'रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र' बताया गया है, जहां 3 या उससे अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ADR ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का सही कारण नहीं बता रहे हैं और 'लोकप्रियता' या 'राजनीतिक बदले की भावना' जैसे आधारहीन कारण दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो पहले फेज में 309 उम्मीदवार (21 प्रतिशत) करोड़पति हैं। सभी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.34 करोड़ रुपये आंकी गई है। पार्टियों के हिसाब से औसत संपत्ति में तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे है, जहां उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5.70 करोड़ रुपये है। इसके बाद भाजपा (2.57 करोड़ रुपये), कांग्रेस (2.06 करोड़ रुपये) और CPI(M) (92.42 लाख रुपये) का स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस के 72 प्रतिशत, बीजेपी के 47 प्रतिशत, कांग्रेस के 33 प्रतिशत और CPM के 24 प्रतिशत उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है। सबसे अमीर उम्मीदवारों में तृणमूल कांग्रेस के जाकिर हुसैन पहले स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति 133 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। इसके बाद 105 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ गौतम मिश्रा दूसरे और 72 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ कबी दत्ता तीसरे नंबर पर आते वहीं, सबसे गरीब उम्मीदवारों में रुबिया बेगम (500 रुपये), सुश्रुता सारेन (700 रुपये) और जशोदा बर्मन (924 रुपये) शामिल हैं। इन तीनों के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।जनसांख्यिकीय आंकड़ों के मुताबिक, कुल उम्मीदवारों में सिर्फ 167 (11 प्रतिशत) महिलाएं हैं। लगभग आधे उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 5 से 12 के बीच है, जबकि 47 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक या उससे ज्यादा शिक्षित हैं। उम्र के हिसाब से 53 प्रतिशत उम्मीदवार 41 से 60 वर्ष के बीच के हैं। ADR की यह रिपोर्ट चुनावी राजनीति में आपराधिक मामलों और धनबल की बढ़ती भूमिका को एक बार फिर उजागर करती है।

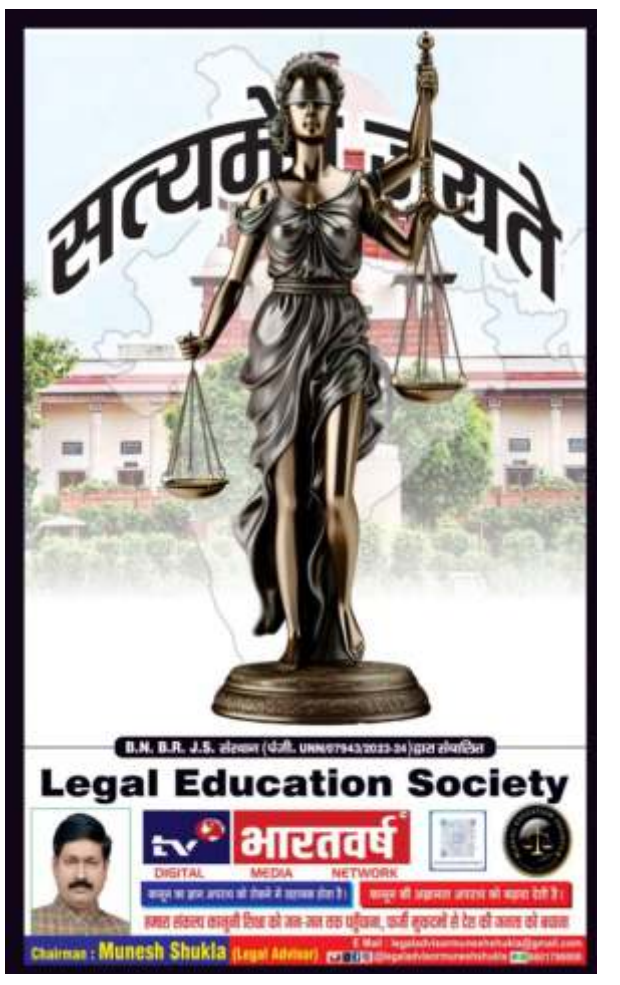

कंपार्टमेंट वाले छात्रों को राहत

छात्रों को एक नहीं बल्कि तीन अवसर मिलेंगे

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दसवीं के रिजल्ट में देशभर में 1, 47, 172 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। सीबीएसई की दो बोर्ड परीक्षा व्यवस्था के तहत कंपार्टमेंट वाले छात्रों को पास होने के तीन मौके मिलेंगे। नई व्यवस्था के तहत जिन छात्रों को दसवीं के नतीजों में कंपार्टमेंट मिली है उन्हें अपना प्रदर्शन सुधारने का पहला मौका मई 2026 में सुधार परीक्षा के रूप में मिलेगा। सफल नहीं होने पर दूसरा मौका फरवरी 2027 और तीसरा एवं अंतिम मौका मई 2027 में दिया जाएगा। इसके बाद भी छात्र पास नहीं होता है, तो उसे सभी विषयों की परीक्षा दोबारा देनी होगी। बोर्ड ने दसवीं पास करने के बाद अतिरिक्त विषय के साथ परीक्षा में बैठने की अनुमति को समाप्त किया है। दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोनों परीक्षाओं (पहली व दूसरी) के लिए फोटोकॉपी, सत्यापन और पुनर्मल्यांकन की ऑनलाइन सुविधाएं दूसरी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध होगी। जो इसका इस्तेमाल ग्यारहवीं में दाखिले के लिए किया जा सकता है। छात्र को दूसरी परीक्षा में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए पहली मुख्य परीक्षा में बैठना अनिवार्य था। अपना प्रदर्शन जो सुधारना चाहते हैं और जिनकी कंपार्टमेंट आई उनकी एलओसी (लिस्ट ऑफ कैंडिडेट) अलग से भरी जाएगी। दूसरी बार की एलओसी में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होगी और 20 अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी होगी। 21 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लेट

फीस के साथ एलओसी तैयार होगी। प्रति विषय के लिए छात्रों को परीक्षा शुल्क के रूप में 320 रुपये का भुगतान करना होगा। तीन विषयों के लिए 960 रुपये देने होंगे। लेट फीस के रूप में अतिरिक्त 2000 रुपये देने होंगे।

महत्वपूर्ण बातें

ऐसे छात्र जो दूसरी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिनके नाम पहले चरण के एलओएसी में प्रस्तुत नहीं किए गए थे, वे अब अपने नाम प्रस्तुत कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

जिन छात्रों के नाम पहले चरण में प्रस्तुत किए जा चुके हैंए वे अब परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।

जिन छात्रों ने पहले अपने नाम प्रस्तुत किए थे, लेकिन वे दूसरी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते, वे अपने नाम वापस ले सकते हैं।

छात्र दूसरी बोर्ड परीक्षा में गणित का विकल्प भी बदल सकते हैं। मुख्य परीक्षा (फरवरी-मार्च) में जिन्होंने गणित स्टैंडर्ड लिया था, वे दूसरी परीक्षा में गणित बेसिक का विकल्प चुन सकते हैं। अन्य चुने गए विषयों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

सभी पास छात्र दूसरी परीक्षा में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी तीन विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

ऐसे छात्र जो ईआर (इंसेंशियल रिपीट) श्रेणी में रखे गए हैं, वे दूसरी परीक्षा में नहीं बैठ सकते।

यदि किसी छात्र का नाम एलओसी में है और शुल्क भी जमा है, लेकिन वह दूसरी परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है, तो मुख्य परीक्षा 2026 में उसका प्रदर्शन अंतिम माना जाएगा।

दूसरी परीक्षा मुख्य परीक्षा 2026 के पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी।

IIT खड़गपुर के AI और लीडरशिप कोर्स शुरू; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

तकनीक की दुनिया तेजी से बदल रही है और अब सीखने का तरीका भी बदल रहा है. ऑफिस में काम करने वाले पेशेवर अब घर बैठे देश के बड़े संस्थान से नई तकनीक सीख सकेंगे. इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आईआईटी खड़गपुर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और टेक्नोलॉजी लीडरशिप से जुड़े चार ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव कोर्स शुरू करने की घोषणा की है.

खास बात यह है कि ये कोर्स खास तौर पर कामकाजी पेशेवरों के लिए बनाए गए हैं, ताकि वे अपनी नौकरी जारी रखते हुए नई तकनीक में महारत हासिल कर सकें. अब कैंपस में आए बिना भी आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसरों से लाइव ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई संभव होगी. कौन-कौन से कोर्स शुरू हुए?

जेनरेटिव A I और एजेंटिक A I में एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट

AI-नेटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग

एप्लाइड AI और मशीन लर्निंग

टेक्नोलॉजी और A I लीडरशिप में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम

इन कोर्स को संस्थान के अलग-अलग विभागों द्वारा तैयार किया गया है, जिनमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग, AI विभाग और पार्थ घोष स्कूल ऑफ लीडरशिप शामिल हैं. पाठ्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि छात्र केवल सिद्धांत ही नहीं, बल्कि असली दुनिया में A I के उपयोग को भी समझ सकें. बड़े लैंग्वेज मॉडल (LLM), जेनरेटिव सिस्टम और एजेंट आधारित तकनीक जैसे विषयों पर खास ध्यान दिया जाएगा

सभी कक्षाएं लाइव ऑनलाइन होंगी. यानी छात्र सीधे आईआईटी खड़गपुर के शिक्षकों से जुड़ सकेंगे. पढ़ाई का तरीका ऐसा रखा गया है कि कामकाजी लोग अपने समय के अनुसार सीख सकें. यह कदम संस्थान की उस सोच को दिखाता है, जिसमें वह कैंपस से बाहर भी अपनी शिक्षा पहुंचाना चाहता है..

विनोद कांबली की मदद के लिए आगे आए सचिन तेंदुलकर

IPL के असली चेज मास्टर हैं श्रेयस अय्यर

124 से अधिक की औसत से बनाए हैं रन

क्रिकेट में जब भी सफल रन चेज की बात होती है तो वहां सबसे पहला नाम जो सभी के मन में आता है वो है विराट कोहली का। फॉर्मेट चाहे कोई भी हो लेकिन रन चेज में विराट का रिकॉर्ड हमेशा ही अच्छा रहा है। लेकिन आईपीएल में पिछले दो साल में रन चेज करते हुए विराट कोहली से ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बना दिए हैं। आईपीएल 2024 से अब तक लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन के मामले में अय्यर ने चेज मास्टर किंग कोहली को पछाड़ दिया है। आईपीएल 2024 से लेकर 16 अप्रैल को हुए MI vs PBKS मुकाबले तक सफल रन चेज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अब श्रेयस अय्यर के नाम हो गया है। उन्होंने इस दौरान 14 पारियों में 621 रन बनाए हैं और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम है। उन्होंने 2024 से अब तक आईपीएल में लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए 11 पारियों में 618 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में जोस बटलर तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 11 पारियों में 549 रन बनाए हैं। वहीं पांचवें नंबर पर प्रभसिमरन का नाम है। उनके नाम 14 पारियों

में 500 रन दर्ज हैं। आईपीएल 2024 से लेकर अब तक सफल रन चेज में श्रेयस अय्यर के आंकड़ों की बात करें तो वहां उन्होंने 14 पारियों में 124.20 के औसत से 621 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 173.5 का रहा है। 14 पारियों में उनके नाम 7 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस दौरान उनके बल्ले से 45 चौके और 39 छक्के आए हैं। इस सीजन भी अय्यर बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं।श्रेयस अय्यर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने इस मैच में 5 चौके और 4 छक्के की मदद से 35 गेंदों में 66 रन की पारी खेली।

गुरुवार को खेले गए मुकाबले में हार्दिक-बुमराह के बीच हुई बहस?

मुंबई इंडियंस के लिए IPL 2026 में अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं रहा है. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली ये टीम लगातार 4 मैच हार चुकी है. टीम में शामिल दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में एक जसप्रीत बुमराह भी बेअसर रहे हैं. टीम 5 मैच खेल चुकी है जबकि बुमराह अभी विकेट का खाता भी नहीं खोल पाए हैं. टीम की स्थिति से तो फैंस परेशान हैं ही, गुरुवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर जो हुआ उससे भी फैंस मायूस हो गए. फील्ड पर बुमराह के ओवर में हार्दिक को गुस्से में फील्डिंग सेट करते हुए देखा गया. वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए थे. क्विंटन डिकॉक ने नाबाद शतकीय पारी खेली थी. मुंबई की गेंदबाजी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई, जसप्रीत बुमराह भी कोई विकेट नहीं ले सके, उन्होंने अपने 4 ओवरों में 10 से अधिक की इकॉनमी से 41 रन दिए.

हार्दिक पांड्या फील्डिंग के दौरान गुस्से में नजर आए. मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह के ओवर में नजर आया कि हार्दिक पांड्या अपनी इच्छा से एक फील्ड बदलना चाहते थे, बुमराह उससे सहमत नहीं थे. लेकिन फिर जल्दी ही बुमराह ने हाथ उठाकर मान लिया. कैमरा तुरंत रोहित शर्मा के ऊपर गया, जिसमें वह भी परेशान दिखे और उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया. फैंस को बुमराह के रिएक्शन से लग रहा है कि उन्हें भी हार्दिक का ये रवैया अच्छा नहीं लगा.

विराट कोहली जर्मन ब्लॉगर लेजला की फोटो लाइक करने को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर फिर से चर्चा में आ गए हैं। पिछली बार जब उनके अकाउंट से टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर की तस्वीर लाइक हो गई थी तो उस समय कोहली ने पूरा ठीकरा इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पर फोड़ दिया था। एक बार फिर विराट कोहली के अकाउंट से कुछ ऐसा हुआ है जो इंटरनेट के जासूसों की पैनी नजरों से बच नहीं पाया है। दरअसल, कोहली ने इस बार फिर किसी की तस्वीर लाइक करके सोशल मीडिया में हलचल मचा दी है। बता दें कि, अवनीत कौर के बाद अब विराट कोहली इस बार एक जर्मन ब्लॉगर लेजला की फोटो लाइक करने को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। हैरानी की बात ये है कि लाइक इसी साल 30 जनवरी की एक पोस्ट पर किया गया है। जिस तस्वीर को लाइक किया गया है उसमें ब्लॉगर स्काई ब्लू रंग की वन पीस ड्रेस में पोज देते हुए नजर आ रही है। वहीं कोहली के इस तस्वीर को लाइक करते ही फैंस ने एल्गोरिदम को लेकर मजे लेना शुरू कर दिया है। फैंस तस्वीर पर लाइक किए हुए का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और हंस रहे हैं। इस दौरान कुछ फैंस अनुष्का शर्मा का भी जिक्र कर रहे हैं। हालांकि, जर्मन ब्लॉगर की तस्वीर को विराट कोहली ने खुद लाइक किया है या वाकई एल्गोरिदम के कारण हुआ है ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इससे पहले अवनीत कौर के मामले में कोहली ने सफाई दी थी। उस दौरान उन्होंने लिखा था कि, मैं ये

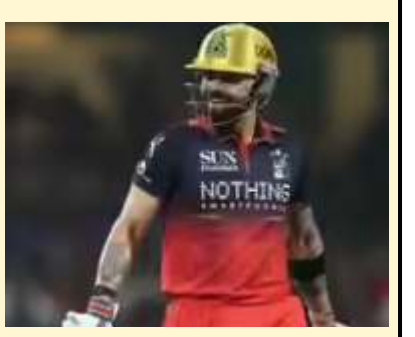

क्लियर करना चाहूंगा कि जब मैं अपनी फीड स्क्रॉल कर रहा था तो ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम ने गलती से किसी इंटरैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया होगा। इसके पीछे मेरा कोई इंटेंसन नहीं था। मैं गुजारिश करता हूं कि बेवजह की अटकलें ना लगाई जाएं।

भारतीय महिला ने बताया पूरा अनुभव

जर्मनी में काम करना नहीं है आसान!

जर्मनी में काम करने को लेकर भारतीयों के बीच एक खास छवि बनी हुई है, जहां बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस और प्रोफेशनल माहौल की उम्मीद की जाती है. लेकिन हाल ही में मोनिका नाम की एक भारतीय महिला ने अपने अनुभव साझा कर इस धारणा पर नई बहस छेड़ दी है.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि जर्मनी का वर्क कल्चर बाहर से जितना परफेक्ट दिखता है, असल में उससे काफी अलग है. मोनिका के अनुसार, जर्मनी में करियर ग्रोथ तेज नहीं बल्कि धीमी और स्थिर होती है. यहां प्रमोशन

एक तय संरचना और समय के अनुसार मिलते हैं, न कि अचानक तेजी से आगे बढ़ने के रूप में. सैलरी में बढ़ोतरी भी सीमित रहती है और नौकरी बदलने पर भी अपेक्षा के अनुसार बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलता. ⊙

इंजीनियर ने बताया जॉब गई तो क्या करेंगे

गूगल से निकाले गए, जवाब से छाए

अमेरिका में रहने वाले एक टेक प्रोफेशनल की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है.उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा है, जिसने हर नौकरी करने वाले इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया.अगर आपको पता हो कि कल आपकी जॉब चली जाएगी, तो आप आज क्या अलग करेंगे.

यह सवाल उस इंजीनियर ने उठाया, जिसे हाल ही में गूगल से नौकरी से निकाल दिया गया. उसने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उसने अपनी नौकरी के दिनों की झलक दिखाई. वीडियो में ऑफिस का माहौल, रोजमर्रा का काम और वह लाइफस्टाइल दिखी, जिसे देखकर लोग इसे परफेक्ट करियर

इंजीनियर ने कहा जीवन की कई चीजें सिर्फ काम के लिए टाल दीं.

मानते हैं. इस वीडियो की असली बात उसके शब्दों में छिपी थी.

उसने लिखा कि उसने हमेशा अपने जीवन में काम को सबसे ऊपर रखा.

उसे लगता था कि अगर वह ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा घंटे काम करेगा और अपनी छुट्टियां टाल देगा, तो उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा.लेकिन जब अचानक उसकी नौकरी चली गई, तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई. उसने कहा कि इतनी मेहनत के बावजूद आखिर में कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहा. उसने यह भी बताया कि आज के समय में कंपनियों का किसी भी समय कर्मचारियों को निकाल देना आम बात बन गई है.यानी चाहे आप कितने भी मेहनती क्यों न हों, जॉब की कोई गारंटी नहीं है. ⊙

लंदन की महिला का वीडियो हो रहा है वायरल

बिहारी स्टाइल में समोसा बेच रही फिरंगी महिला!

महिला ने ऑनलाइन अपना नाम गोरिया देवी रखा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह बिहारी समोसा वाले की दुकान में समोसा फ्राई करते और बेचते दिख जाती हैं. वीडियो में वो खुद को एक बिहारी लड़की बताती रहती है. वह कहती हैं कि गोरे रंग पर मत जाना, दिल से मैं एक बिहारी हूं.

इन दिनों इंटरनेट पर बिहारी समोसा वाला के बाद गोरिया समोसा वाली वायरल हो रही है. यह फिरंगी महिला लंदन में बिहारी समोसा वाले के साथ जुड़कर काम कर रही है और बिहारी लहजे में ही रील्स बना-बना कर अपनी दुकान और काम का प्रचार कर रही है.

बिहारी लहजे में बात करती विदेशी महिला के वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. ठेठ

लंदन की सड़कों पर बिहारी लहजे में समोसा बेच रही विदेशी महिला.

बिहारी लहजे में लंदन की सड़कों पर समोसा बेचती गोरी मेम का वीडियो काफी वायरल होता रहता है. वह हर दिन समोसा बेचने के नए-नए ट्रिक बताते और रोल प्ले करती दिखती है. इस फिरंगी महिला ने ऑनलाइन अपना नाम गोरिया देवी रखा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह बिहारी समोसा वाले की दुकान में समोसा फ्राई करते और बेचते दिख जाती हैं. वीडियो में वो खुद को एक बिहारी लड़की बताती रहती है. वह कहती हैं कि गोरे रंग पर मत जाना, दिल से मैं एक बिहारी हूं. हर वीडियो में वह बिहारी लहजे में पंच लाइन बोलते और समोसा बेचते दिखाई देती है. एक तरह से वो बिहारी समोसे वाले की नकल ही करती है. क्योंकि, लंदन में बिहारी समोसा वाला अपने अंदाज की वजह से काफी फेमस हुआ है और उसकी यही यूएसपी उसकी विदेशी साथी भी इस्तेमाल कर रही है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @ biharisamosa.uk नाम के हैंडल से यह विदेशी महिला वीडियो बना-बनाकर शेयर करती रहती है. इन वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में बिहारी समोसा वाले के दो दुकान का पता भी रहता है. इस विदेशी महिला के बिहारी अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. लंदन में समोसा बेचने वाली एक महिला के भारत में भी काफी फैन फॉलोइंग है. ⊙

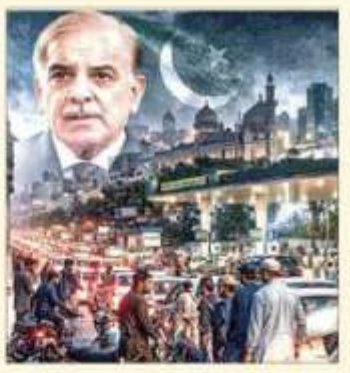

लॉकडाउन जैसे नियमों पर भड़के पाकिस्तानी

पाकिस्तान की सरकार के सितारे शायद ही कभी सीधे चलते हों और जनता हर बार उसी गर्दिश में पिसती नजर आती है. इस वक्त भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. एक तरफ अफगानिस्तान सीमा को लेकर तनाव बना हुआ है, तो दूसरी ओर शहबाज शरीफ सरकार की नीतियों से लोग नाराज हैं. ऊपर से मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट ने ऐसा असर डाला है कि तेल के कीमतों में आग लग गई है. ⊙

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया सख्त आदेश, कार्तिक आर्यन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा का आदेश दिया

बॉलीवुड के 'शहजादा' कार्तिक आर्यन अब उन चुनिंदा सितारों की फेहरिस्त में शामिल हो गए हैं, जिन्हें अपने नाम, चेहरे और आवाज के इस्तेमाल पर कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। ऐश्वर्या राय बच्चन, सलमान खान और करण जौहर के बाद, बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कार्तिक आर्यन के 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्तिक की तस्वीरों और इमेज का बिना अनुमति के व्यावसायिक (Commercial) इस्तेमाल करना अब अपराध माना जाएगा। 'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस शर्मिला देशमुख ने कहा कि वह कार्तिक आर्यन के पक्ष में आदेश पारित करेंगी। जो लोग इस बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि यह कदम तब उठाया गया, जब कार्तिक आर्यन के वकील, सीनियर वकील बीरेंद्र सराफ ने ऐसे कंटेंट की ओर कोर्ट का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ कंटेंट अपमानजनक (scandalous) था, और कुछ का इस्तेमाल मर्चेंडाइज़ (सामान) बेचकर पैसे कमाने के लिए किया जा रहा था। कार्तिक आर्यन के पर्सनैलिटी राइट्स के कई कथित गलत इस्तेमाल की ओर इशारा करते हुए, उनके वकील, सीनियर वकील बीरेंद्र सराफ ने कहा, "मैं चाहता हूँ कि वही आदेश पारित हो, जिस पर आपकी लॉर्डशिप (जज साहिबा) ने पहले विचार किया था—कि जब मैं उन्हें किसी कंटेंट के बारे में बताऊँ, तो वे उसे हटा दें। मैं यह नहीं चाहता कि वे खुद से (suo motu) कोई जाँच-पड़ताल करें। मुझे जिस भी कंटेंट के बारे में पता चलेगा, मैं उन्हें बताता रहूँगा, और वे उसे हटा सकते हैं। वह एक जाने-माने एक्टर हैं; उनके नाम का भी ट्रेडमार्क है। उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल मर्चेंडाइज़ बेचने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाए गए वीडियो भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ कंटेंट काफी खराब है, और कुछ उनकी पर्सनैलिटी पर बुरा असर डाल रहा है। कुछ कंटेंट तो बेहद अपमानजनक है।" अपनी याचिका में, कार्तिक आर्यन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सरकारी अधिकारियों को यह निर्देश देने की भी माँग की है कि वे ऐसे कंटेंट को हटाएँ, जो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करता है, और साथ ही उन गुमनाम अपराधियों की पहचान उजागर करें, जो ऐसा कर रहे हैं।कार्तिक आर्यन के अलावा, बॉलीवुड के कई अन्य सितारों ने भी अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इनमें अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, करण जौहर, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार शामिल हैं। इन सितारों में से कई लोगों द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर कोर्ट ने आदेश भी पारित किए हैं। फिल्मों की बात करें तो, कार्तिक आर्यन आखिरी बार रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा' में अनन्या पांडे के साथ नज़र आए थे। वह अगली बार मृगदीप लांबा के क्रिएचर ड्रामा 'नागज़िला' में नज़र आएंगे, जिसे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस का समर्थन प्राप्त है।

मायावती का विपक्ष पर हमला

SC-ST-OBC के मुद्दे पर दल बदलते हैं रुख

बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने SC, ST और OBC समाज के हितों की अनदेखी की।उन्होंने कहा कि अब यही पार्टियां महिला आरक्षण के नाम पर इन वर्गों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।मायावती ने लोगों को "दोहरे चरित्र वाली" पार्टियों से सावधान रहने और आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर कहा कि सत्ता में रहने पर कांग्रेस ने कभी भी एससी-एसटी और ओबीसी समाज के हितों का ध्यान नहीं रखा और अब इन वर्गों की महिलाओं की बात कर रही है। इसी तरह सपा का भी एससी-एसटी और ओबीसी के प्रति सत्ता में रहने पर तिरस्कारपूर्ण रवैया रहता है। देश के अनुसूचित जाति-जनजाति व पिछड़े समाज के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के मामले में कांग्रेस गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने पार्टी भी महिला आरक्षण में, जो अब इन वर्गों की बात कर रही है, वो यही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपनी केन्द्र की सरकार के रहते हुये किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं की। तथा ना ही ओबीसी समाज हेतु मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी नौकरी व शिक्षा के क्षेत्र में 27 प्रतिशत आरक्षण को भी लागू किया जिसे फिर बसपा के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार में अनततः लागू किया गया था, जो सर्वविदित है। इसी प्रकार, यूपी में पिछड़े मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ देने के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में ही आई रिपोर्ट को भी सपा सरकार ने ठण्डे बस्ते में डालकर इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर यहां बसपा की दिनांक 3 जून सन 1995 में पहली बनी सरकार ने इसे तुरन्त लागू किया। अब यही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनैतिक स्वार्थ में इनकी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है। इस प्रकार, अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी सपा जब सरकार में नहीं है तो अलग रवैया अपना रही है, किन्तु जब सरकार में होती है तो अलग संकीर्ण जातिवादी व तिरस्कारी रवैया अपनाती है। अतः इन सभी वर्गों को ऐसी सभी छलावा एवं दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से हमेशा सावधान रहना होगा तभी कुछ बेहतर संभव हो पाएगा। जहां तक महिला आरक्षण के लिए पिछली (सन् 2011) जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का सवाल है तो इस बारे में यही कहना है कि यदि इसे जिन भी कारणों से जल्दी लागू करना है तो फिर इसी जनगणना के आधार पर करना है और यदि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी केन्द्र की सत्ता में होती तो फिर यह पार्टी भी बीजेपी की तरह ही यही कदम उठाती। कुल मिलाकर, कहने का तात्पर्य यह है कि देश में एससी, एसटी व ओबीसी एवं मुस्लिम समाज के वास्तविक हित, कल्याण व उनके भविष्य संवारने आदि के किसी भी मामले में कोई भी पार्टी गम्भीर नहीं रही है। इसीलिये महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिये और इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जायेगा अर्थात इन्हें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है क्योंकि इनको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाना है। यही सलाह है।

लखनऊ में बढ़ता जा रहा स्मार्ट मीटर का विरोध

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में स्मार्ट मीटर का विरोध बढ़ता जा रहा है। गुरुवार दोपहर इंदिरानगर के लोगों का आक्रोश सेक्टर-14 के पावर हाउस में फूट पड़ा। लोगों ने वहां पहुंचकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए।करीब एक घंटे तक पावर हाउस में प्रदर्शन किया तो अधिकारियों ने कहा कि चलिए समस्या देखते हैं। इसके बाद वे पैदल ही प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ उनके गांव तक 1 किमी पैदल गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे बिल जमा करते हैं तो कुछ ही देर में उनका बिल माइनस में हो जाता है। राजाबाजार के पार्षद राहुल मिश्रा का लोगों ने घेराव किया। पार्षद ने कहा-जनता परेशान है। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। अधिकारियों से बात कर शिकायत की गई है, लेकिन उनकी तरफ से समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। स्मार्ट मीटर हटाया जाना चाहिए। नेता पार्षद दल कांग्रेस ममता चौधरी ने स्मार्ट मीटर के कारण आ रहे गलत बिल से पीड़ित हबीबनगर, मालवीयनगर, दारुगोदाम के उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए शिकायती पत्र व दस्तावेज के साथ साथ पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ अधीक्षण अभियंता वाणिज्यिक मध्य जोन को ज्ञापन दिया। अधीक्षण अभियंता ने कल से चेक मीटर लगाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। लखनऊ में स्मार्ट मीटर के विरोध में जमकर विवाद हुआ। गुरुवार को लोगों ने स्मार्ट मीटर का अधिक बिल आने पर पार्षद ऑफिस का घेराव किया। इसमें महिलाओं के साथ में स्थानीय पुरुष और अन्य लोग शामिल थे। इन लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर जबरन लगा दिए गए। इसके कारण समस्या बढ़ गई है। अब मीटर की रीडिंग अधिक आ रहा है। राजाबाजार के पार्षद राहुल मिश्रा ने कहा कि लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे।

आग में खोए बच्चे मिलते ही छलक पड़े आंसू

रहमान बोले—'यह हमारे लिए नई जिंदगी है'

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

'आग लगने के बाद हमारे दोनों बच्चे लापता हो गए। जैसे-जैसे आग बढ़ती जा रही थी, वैसे-वैसे हमारी उम्मीद घटती जा रही थी। हम और पत्नी बच्चों को सब जगह ढूंढ़ चुके थे, मगर वे कहीं नहीं मिल रहे थे। हम रोने और चीखने लगे। ऐसा लगा कि दोनों बच्चों को खो दिया। क्योंकि आग इतनी ज्यादा थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच आप लोगों ने हमारी खबर चलाई फिर जानकारी मिली कि हमारे बच्चे जहां आग लगी है, उसके दूसरी तरफ हैं। देर रात दोनों मिल गए। इनका मिलना हमें नई जिंदगी मिलने के बराबर है।' यह कहना था रहमान का, जिनके दो बच्चे आग के बीच लापता हो गए थे। उनकी आंखू में खुशी के आंसू थे। लखनऊ के विकास नगर में 15 अप्रैल को लगी आग में 250 से ज्यादा झुग्गी-झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। कई ऐसे परिवार थे, जिनके बच्चे लापता हो गए थे। उन्हीं मे से एक रहमान भी थे, जिनके बच्चे समीर और आलिया भी लापता हुए थे। बच्चों के लापता होने के बाद दैनिक भास्कर ने रहमान की चीख को प्रमुखता से जगह दी। बाद में बच्चे मिल गए तो रहमान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनसे पूछा कि हादसे वाले दिन 4 बच्चों के लापता होने की बात क्यों कही थी? तो उन्होंने कहा- मैं अपने दोनों बच्चों के खोने से इतने दुख में था कि गलती से 4 बच्चे कह दिया। बच्चों के मिलने के बाद रहमान ने बताया कि देर रात हमें पता चला वो दूसरी तरफ है। बेटा 5 साल का रहीम और बेटी 6 साल की आलिया लापता हुए थे। बच्चों के लापता होने की खबर चलने के बाद हमें किसी ने बताया गया कि बच्चे सुरक्षित हैं। आप आकर ले

जाइए। बच्चों के लापता होने के बाद हम बिल्कुल बेसुध हो गए थे। बच्चों के लापता होने के बाद हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हम यही सोच रहे थे की कहीं बच्चों जल न गए हो। माहौल से बुरी तरह डरे हुए थे। रहमान ने बताया कि अभी 4 महीने पहले ही हमारे बड़े बेटे की बीमारी से मौत हो गई थी जिसकी उम्र 12 साल थी। अगर इन बच्चों को भी कुछ हो जाता तो हम यह सदमा बर्दाश्त न कर पाते। हम इन्हीं के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर यही न होते तो हम क्या करते? आज हमारी सारी पूंजी जलकर राख हो गई मगर उसका इतना अफसोस नहीं है। उससे ज्यादा हमको बच्चों के मिलने की खुशी ज्यादा है। फिलहाल, हम अपना गम भूल गए हैं और बच्चे मिल गए, यही हमारे लिए सब कुछ है।

भतीजे का घर बचाने के लिए आग में कूदे चाचा की मौत

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

यूपी के गोंडा में भतीजे का घर बचाने के लिए आग में कूदे चाचा की मौत हो गई। घटना से गांव में मातम का माहौल है। अस्पताल से मौत की खबर आई तो घर में चीख पुकार मच गई। ग्रामीण परेशान परिजन को ढांढस बंधाते रहे। घटना मोतीगंज थाना क्षेत्र के पिपरा भिटौरा के मजरे रमवापुर गांव की है। गांव निवासी सोनू के छप्परनुमा घर में शनिवार को शाम करीब 5 बजे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। घर में रखे रसोई गैस सिलिंडर में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि सिलिंडर करीब 300 मीटर दूर जा गिरा। धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। धमाके के बाद सोनू के चाचा श्याम लाल (60) अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। भतीजे का घर बचाने के लिए वह आग की लपटों के बीच घुस गए। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने उन्हें निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया।

इलाज के दौरान बृहस्पतिवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उधर, आग से घर में रखे करीब 60 हजार रुपये नकद, जेवर, कपड़े, अनाज समेत गृहस्थी का सामान जलकर गया। लेखपाल नागेंद्र प्रताप के अनुसार, आग से करीब 2.5 लाख रुपये की क्षति का अनुमान है। एसडीएम सदर अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़ित परिवार को शासन की ओर से राहत दिलाई जाएगी। दैवीय आपदा राहत मद से चार लाख रुपये और किसान दुर्घटना बीमा के तहत पांच लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है।

लखनऊ नगर निगम के संपूर्ण समाधान दिवस में 191 शिकायतें

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

नगर निगम मुख्यालय में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में नागरिकों की कुल 191 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें सबसे अधिक 84 शिकायतें हाउस टैक्स से संबंधित रहीं, जबकि जलकल विभाग से जुड़ी 8 शिकायतें प्राप्त हुईं। कार्यक्रम में मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड के हरिओम नगर क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग सड़क और जलभराव की समस्या लेकर पहुंचे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में सड़क न होने के कारण लगातार जलभराव की स्थिति बनी रहती है, जिससे आपसी विवाद बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस समस्या के कारण तनाव बढ़ा और एक व्यक्ति ने मानसिक दबाव में आत्महत्या तक कर ली। इस दौरान स्थानीय पार्षद नरेश रावत भी शिकायतकर्ताओं के साथ पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र में सड़क और नालियों के निर्माण के लिए विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह का पत्र मेयर को सौंपा, हालांकि बाद में यह पत्र वापस कर दिया गया। हरिओम नगर की निवासी गुड़िया ने बताया कि इलाके में न तो सड़क बनी है और न ही उचित नाली व्यवस्था है, जिससे घरों के आसपास लगातार जलभराव रहता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के कारण लोगों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं और जीवन मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी कोमल श्रीवास्तव ने बताया कि गली में जल निकासी की व्यवस्था न होने से हालात और खराब हैं।

लखनऊ के छात्र बोले-

कभी समय देखकर पढ़ाई नहीं की

स्वस्ति जैन ने बताया कि उनके पिता सन्मति कुमार जैन GST के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। अभी बदायूं में तैनाती है। उनकी मां सरिता जैन गृहणी है। छोटी बहन श्रेयसी 8वीं में पढ़ रही हैं। परीक्षा की तैयारी के सवाल पर वो कहती हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए उन्होंने अलग से कोचिंग जॉइन की थी। रोजाना 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करती थी। सोशल मीडिया या ऑनलाइन समय वेस्ट नहीं किया। रेगुलर स्टडी से सालभर पढ़ाई की। 99.2% स्कोर हासिल करने के बाद स्वस्ति कहती हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि कम से 99.6% मिलेंगे। उन्हें 2 सब्जेक्ट्स में कम नंबर मिलना खलता है। हालांकि, इस बात की खुशी थी कि उन्हें मैथ्स और AI में पूरे नंबर यानी 100 में 100 मिले हैं। जबकि इंग्लिश और साइंस दोनों में ही 98 नंबर मिले है। भविष्य के लक्ष्य को लेकर उनका कहना हैं कि 11वीं में उन्होंने PCM लिया हैं। आगे चलकर वो JEE क्वालीफाई करना चाहती हैं। फिर ISRO में जाने का उनका लक्ष्य हैं। वो देश के लिए सैटेलाइट और राकेट बनाना चाहती हैं। RLB की इंदिरा नगर की सेक्टर C ब्रांच की स्टूडेंट अविका यादव को 98.2% मार्क्स मिले हैं। उनके पिता दया राम यादव और मां ललिता यादव बेटी की सफलता पर बेहद खुश हैं। अविका कहती हैं कि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए इसलिए उन्होंने ऑनलाइन या किसी सोशल मीडिया हैंडल पर अपना टाइम नहीं वेस्ट किया। खुद का मोबाइल भी नहीं हैं। कभी जरूरत हुई तो मां या पापा के मोबाइल से काम चला लिया। अविका कहती हैं कि उन्होंने JEE की तैयारी के लिए कोचिंग की थी इसके अलावा उनका ज्यादातर फोकस सेल्फ स्टडी पर था। LPS (सीपी सिंह) साउथ सिटी ब्रांच की छात्रा अनवी द्विवेदी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99% हासिल कर शानदार सफलता पाई है। अनवी बताती हैं कि शुरुआत में वह रोज स्कूल के बाद तीन-चार घंटे सेल्फ स्टडी करती थीं, जबकि परीक्षा के नजदीक आते ही पढ़ाई का समय बढ़ाकर 5 से 6 घंटे कर दिया। उन्होंने पुराने साल के प्रश्न पत्र और टेस्ट पेपर हल कर अपनी तैयारी मजबूत की। उन्हें आईआईटी में जाना है। उनके पिता मनोज कुमार द्विवेदी ED में कार्यरत हैं और मां पूनम द्विवेदी गृहिणी हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने न के बराबर ही कोई पढ़ाई की थी। RLB

की आदित्री गुप्ता को 98.4% मार्क्स मिले हैं। वो कहती हैं कि साइंस के पेपर में उनसे एक ब्लंडर हो गया था। इसलिए उनके कुछ नंबर कम हो गए। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य सिविल सर्विस हैं पर पहले वह बीटेक करना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने मैथ्स स्ट्रीम को चुना हैं।

उन्नाव में सगाई के बाद दोहरी मौत:

युवक ने दी जान, तानों से आहत मंगेतर ने भी जहर खाया

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव। गुरुवार को दोपहर में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। लड़के की मौत की सूचना जैसे ही लड़की के घर पहुंची तो वह पिता के साथ मंगेतर के घर पहुंच गई। यहां महिलाओं ने उसे ताने दिए और मौत का जिम्मेदार ठहराया। घर लौटकर देर रात लड़की ने भी जहर खाकर जान दे दी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। वाट्सएप मैसेज के कारण लड़का और लड़की ने सुसाइड कर लिया। 16 फरवरी को दोनों की इंगेजमेंट हुई थी। बताया जा रहा है कि लड़की के प्रेमी ने एक सप्ताह पहले होने वाले पति के फोन पर कुछ फोटो-वीडियो भेजे थे, जिसके बाद दोनों में इसको लेकर झगड़ा चल रहा था। पूरा मामला अचलगंज थाना क्षेत्र का है। गौरी गांव के रहने वाले महेश और उनकी पत्नी शिक्षामित्र हैं। घर में बेटे सूरज उर्फ भोला (25) के अलावा एक छोटा बेटा और बेटी हैं। सूरज बीएससी और आईटीआई करने के बाद गांव में रहकर खेती-किसानी कर रहा था। वहीं राजापुर गांव के रहने वाले संतोष की बेटी कोमल (23) 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद घर पर सिलाई-कढ़ाई का काम करती थी। दो छोटी बहन काजल-सुनैना और एक छोटा भाई शिवम हैं। सूरज और कोमल के गांव की दूरी करीब 10 किमी है। 16 फरवरी को घर वालों की मर्जी से सूरज की इंगेजमेंट कोमल के साथ हुई थी। नवंबर में शादी की तैयारी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। इंगेजमेंट के बाद से दोनों में फोन पर बातचीत होती थी। नवंबर में शादी करने की तैयारी थी। सब कुछ सही चल रहा था तभी करीब एक सप्ताह पहले सूरज के व्हाट्सएप नंबर पर कुछ अश्लील मैसेज आए थे। मैसेज करने वाले ने खुद को कोमल का प्रेमी बताया था और शादी तोड़ने का दबाव बना रहा था। इन मैसेज के बाद सूरज ने कोमल से इसके बारे में पूछा तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। घर वालों को भी इसकी जानकारी हो गई और सभी लोग मामले को सुलझाने में लगे हुए थे। फोटो-वीडियो देखने के बाद से सूरज काफी तनाव में था। गुरुवार को उसने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी कोमल के घर पहुंची तो पिता के साथ वह सूरज के घर आई थी। यहां घर और गांव वालों ने उसे बुरा-भला कहा और बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया। इसके बाद पिता-पुत्री अपने घर लौट गए। घर पहुंचने के बाद कोमल गहरे सदमे में चली गई। रात करीब 11 बजे उसने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर घर वालों को जानकारी हुई तो एक निजी अस्पताल में लेकर गए। यहां इलाज के दौरान देर रात करीब 1 बजे उसकी मौत हो गई। कोमल के पिता संतोष ने बताया कि गुरुवार सुबह सूरज ने परिवार में हुए किसी विवाद के बाद अपने ही घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। जानकारी मिलने पर मैं सूरज के घर जा रहा था। कोमल ने भी साथ चलने की जिद की तो उसे भी ले गए। वहां मौजूद महिलाओं ने कोमल को सूरज की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे भला-बुरा कहा था। यह बात उसके दिल पर लग गई। कुछ देर में बेटी को लेकर घर आ गए। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तभी कोमल को उल्टियां होने लगीं। हम लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए, यहां उसकी मौत हो गई। पिता के अनुसार तानों से आहत होकर कोमल ने जान दी है।

मेट्रोमोनियल साइट से ठगी 35.11 लाख वापस कराए

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

सदर कोतवाली के सिविल लाइन मोहल्ला निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर विनीता द्विवेदी ने अपनी डॉक्टर बेटी की शादी के लिए मेट्रोमोनियल साइट पर लड़का देखा था। लड़के के पिता ने शादी के अलग-अलग संस्कारों के नाम पर उनसे 75,11,353 रुपये विभिन्न माध्यमों से अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। रुपये देने के करीब 45 दिन बाद उन्हें ठगी का पता चला। 17 जनवरी 2026 को उन्होंने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। साइबर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी से ली गई धनराशि को पीड़िता के संबंधित खातों में फ्रीज कराया। इसके बाद संबंधित बैंक के जरिए पत्राचार कर 35,11,101 रुपये पीड़िता के खाते में वापस कराए। प्रभारी निरीक्षक राजेश पाठक ने बताया कि शेष धनराशि को भी वापस कराने का प्रयास किया जा रहा है।

'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को लेकर जागरूकता कार्यक्रम

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में केंद्र सरकार के 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विकास भवन सभागार में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका सुधा शुक्ला और सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज शामिल हुए। सिटी मजिस्ट्रेट ने विधेयक के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 106वें संविधान संशोधन के तहत यह अधिनियम लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल कर देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षिका सुधा शुक्ला ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होंगी और हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आएंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। ग्रामीण क्षेत्रों तक इस विधेयक की जानकारी पहुंचाने पर भी विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने बताया कि ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और स्थानीय निकायों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों, विशेषकर महिला प्रधानों के जरिए गांव-गांव तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। 'मिशन शक्ति' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव स्तर तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज के समग्र विकास को गति दी जा सके।

अचलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कोरारी खुर्द में पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद

उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कोरारी खुर्द में पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। छोटे भाई समरवीर सिंह ने अपने बड़े भाई ब्रजपाल सिंह उर्फ बबलू सिंह पर संपत्ति का हिस्सा न देने और घर बनाने में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। समरवीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पिता स्वर्गीय लल्ला सिंह की संपत्ति का आपसी सहमति से बंटवारा हो चुका है। इस बंटवारे में उन्हें एक-तिहाई हिस्सा मिला था, जिसे गांव के सम्मानित लोगों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में तीन बार तय किया गया था। आरोप है कि बंटवारे के बावजूद बड़े भाई ब्रजपाल सिंह और उनके परिवार द्वारा उन्हें न तो रहने की जगह दी जा रही है और न ही अपने हिस्से में घर बनाने दिया जा रहा है। समरवीर का कहना है कि जब भी वह निर्माण कार्य शुरू करते हैं, तो ब्रजपाल सिंह, उनकी पत्नी और अन्य परिजन मौके पर पहुंचकर गाली-गलौज करते हैं और काम रुकवा देते हैं। समरवीर ने यह भी आरोप लगाया कि कई बार डायल 112 पुलिस को बुलाकर भी उनके निर्माण कार्य को रुकवाया गया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर भी कार्य में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। प्रार्थी का कहना है कि विरोधी पक्ष उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दे रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हैं। इस संबंध में समरवीर सिंह पहले भी क्षेत्राधिकारी बीघापुर और थाना अचलगंज में कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि उनके हिस्से में घर निर्माण कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा कराने की अनुमति दी जाए और विरोधी पक्ष द्वारा की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

नारी शक्ति वंदन अभियान पर भव्य कार्यक्रम

महिला आरक्षण अधिनियम-2023 को मिला जोरदार समर्थन

कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अतुल वत्स, पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा, मुख्य विकास अधिकारी पी0एन0दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक रामानंद कुशवाहा, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जनपद की प्रतिष्ठित महिलाएं, मातृ शक्ति, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकार बंधु आदि उपस्थित रहें।

हाथरस 17 अप्रैल, 2026 महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सम्मान हेतु नारी शक्ति वन्दन अभियान के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, जन-जागरण एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 (महिला आरक्षण अधिनियम-2023) के जमीनी स्तर पर व्यापक समर्थन हेतु जनपद की प्रभावी एवं प्रतिष्ठित मुख्य महिला अतिथियों यथा अधिष्ठात्री, प्रवक्ता, चिकित्सक, अधिवक्ता तथा सहायक अध्यापिका एवं जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में कार्यक्रम/प्रेस वार्ता का आयोजन पुलिस लाइन्स ऑडिटोरियम, हाथरस में किया गया। कार्यक्रम के दौरान जनपद की प्रभावी एवं प्रतिष्ठित महिलाओं यथा डॉ0 पवित्रा विद्या अलंकार, अधिष्ठात्री, कन्या गुरुकुल सासनी, श्रीमती प्रियंका सरोज, प्रोफेसर आर0डी0 डिग्री कॉलेज, डॉ0 दीपिका शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ, अधिवक्ता सुश्री ऋतु गौतम तथा सहायक अध्यापिका नीलम देवी ने अपने-अपने संबोधन के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि नारी शक्ति वन्दन अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है। नारी शक्ति वन्दन अभियान का शंखनाद दिनांक 16 अप्रैल, 2026 से पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 (महिला आरक्षण अधिनियम-2023) के सन्दर्भ में अत्यन्त ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यह सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय का प्रतीक होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023, (महिला आरक्षण अधिनियम-2023) मार्च, 2023 को महिला दिवस पर श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। 19 सितबर, 2023 को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित किया गया। मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 (महिला आरक्षण अधिनियम-2023) को 28 सितंबर 2023 को मा0 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। जो नए संसद भवन में पारित पहला विधेयक बना। उन्होंने कहा कि 1952 में लोकसभा में मात्र 22 महिलाएं थी, अब 75 से अधिक है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 17 प्रतिशत तक पहुंचा है। यह अधिनियम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। यह अधिनियम महिलाओं को केवल मतदाता नहीं, बल्कि नीति-निर्माता बनने का अवसर देता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल आरक्षण का कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान, अधिकार और नेतृत्व का नया अध्याय है। यह अधिनियम महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में सहायक होगा। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर भी लागू होगा। इससे संसद और विधान सभाओं में महिलाओं की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी सीमित है, जबकि इस कानून के बाद यह लगभग एक-तिहाई तक पहुंच सकती है। महिलाओं की भागीदारी बढने से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा जैसे मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलेगी। पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के आरक्षण के सकारात्मक परिणाम पहले ही देखे जा चुके हैं। ग्रामीण और शहरी दोनो क्षेत्रों की महिलाओं को नेतृत्व का नया अवसर मिलेगा। इससे राजनीति में पुरुष और महिला के बीच संतुलित प्रतिनिधित्व स्थापित होगा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी। यह अधिनियम आने वाली पीढ़ी की महिलाओं को राजनीति और नेतृत्व के लिए प्रेरित करेगा। यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार देता है। यह कानून देश के विकास में महिलाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाएगा। यह अधिनियम महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। यह अधिनियम नई पीढ़ी की बेटियों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। महिला जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षिकाओं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की भागीदारी इस अभियान को और प्रभावी बनाएगी। यह अधिनियम महिलाओं के सम्मान, समानता, सुरक्षा और नेतृत्व के नए युग का प्रतीक बनेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति को राष्ट्र के नेतृत्व में सहभागी बनाने के ऐतिहासिक निर्णय हेतु मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि-कोटि आभार। आपका यह कदम विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाएगा।प्रेस वार्ता के दौरान जनपद की प्रभावी एवं प्रतिष्ठित महिलाओं ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने से उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और वे नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी, तो नीतियां अधिक संवेदनशील, समावेशी और समाज के हर वर्ग के हित में होंगी। यह अधिनियम न केवल वर्तमान की महिलाओं को सशक्त करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह पहल "सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि एक सशक्त नारी ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है।कार्यक्रम के मौके पर कन्या गुरुकुल सासनी की छात्राओं शिखा आर्या कक्षा 12, झांसी की रानी की वीरता पर आधारित कविता, श्रिया आर्य ने कविता का पाठ, श्रुति आर्य ने नारी शक्ति पर आधारित कविता "नारी आयो बोलो" पर आधारित कविता का पाठ किया तथा संगीत विद्यालय की टीम ने मातृ शक्ति पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर श्रीमती सुनीता मिश्रा प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र ने मिशन शक्ति तथा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में विचार साझा किये। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने सोशल वर्कर नितिन वर्मन, वैष्णो देवी, फ्री ऐजूकेशन सोनू यादव, प्रभारी वन स्टॉप सेंटर मनीषा भारद्वाज, छात्रा अंशिका दीक्षित तथा महिला पुलिस कर्मियों यथा रुचि, रीना यादव, कामिनी, नेहा, बबली चौधरी, कविता चौधरी तथा प्रेमलता को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल

आयुष और होम्योपैथी के क्षेत्र में भी आगरा बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल खोला जाएगा। ये प्रदेश में पहला आयुष इंस्टीट्यूट होगा। ये 400 बेड का होगा और ये करीब 14 एकड़ जमीन में बनेगा। इसमें कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय रोग का बिना सर्जरी के उपचार होगा। केंद्र सरकार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आगरा में इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके निर्माण के लिए रुनकता के अकबरा गांव में 13.5 एकड़ जमीन भी अधिकृत हो गई है। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें 400 बेड होंगे। आईसीयू भी होगा। चिकित्सकों के लिए चैंबर भी होंगे। ओपीडी, दवा काउंटर, लैब भी होगी। आयुष, यूनानी, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा और योग केंद्र होगा। इसमें आयुष चिकित्सा की पढ़ाई होगी। कैंसर, किडनी, लिवर, हृदय रोग, पेट रोग समेत अन्य जटिल बीमारियों का उपचार किया जाएगा। ऐसे में मरीजों के सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास बात इसमें बीमारियों के लिए शोध कार्य भी किए जाएंगे। ऐसे में देश भर से मरीज इलाज कराने पहुंचेंगे। इंस्टीट्यूट में चार पैथी की पढ़ाई और इलाज की सुविधा होगी। इसमें आयुष, होम्योपैथिक, यूनानी और नेचुरोपैथी की 60-60 सीटें होंगी। इनके लिए अलग-अलग परिसर बनेंगे। इसमें 100-100 बेड होंगे। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए अलग से चैंबर होंगे। पर्चा समेत दवा काउंटर और जांच की सुविधा होगी।

कल्याण सिंह बाबूजी की प्रतिमा पर हुआ पथराव लोधी समाज के लोगों में आक्रोश

उत्तर प्रदेश हाथरस सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव नगला मसंद में आज दिन शुक्रवार दिनांक 17 अप्रैल 2026 को जब सुबह लोग नींद से जागे और आपने खेतों पर घूमने के लिए गए तो रास्ते के पास खड़ी कल्याण सिंह बाबूजी की प्रतिमा को देखकर लोधी समाज के लोगों में आक्रोश छा गया सूचना पर इलाका पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और बाबूजी की प्रतिमा को लेकर पुलिस छानबीन में जुटीबताया जाता है कि बीती रात कुछ लोगों ने बनी हुई नगला मसंद में सड़क के पास कल्याण सिंह बाबूजी की मूर्ति पर पथराव कर दिया जिससे कल्याण सिंह बाबूजी के कान पर पत्थर के निशान देखने को मिलेजब लोग सुबह अपने-अपने खेतों पर घूमने के लिए आए तो बाबूजी की प्रतिमा के आसपास ईट पत्थर देखकर लोग हैरान हो गए और वहां पर खड़े होकर देखने लगे देखते ही देखते लोगों की सकल भीड़ में बदल गई जहां सूचना मिलने पर इलाका पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पथराव की जानकारी लोगों से जुड़ाने लगी कुछ लोगों के कहने के अनुसार जाटव समाज के लोगों की तरफ संकेत करते हुए बताया गया है कि रात पायदा पुर में भीम बाबा साहब के रसिया दंगल हुआ था और वहां से वापसी के समय जाटव समाज के लोगों ने बाबूजी कल्याण सिंह की प्रतिमा पर पथराव किया है फिलहाल में लोगों के द्वारा जांच की मांग और दोषियों पर कार्रवाई अब देखना यह होगा जांच के द्वारा दोषियों तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं।

पोस्टर और झंडा के विवाद ने हिंसा का रूप धारण कर लिया

वाराणसी कमिश्नरेट के चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया में आंबेडकर और केशरिया झंडा उतारने को लेकर दूसरे दिन भी बवाल हो गया। दोनों संगठनों के विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई। जिसमें एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना का सिर फट गया। घटना के बाद घायल एसीपी सारनाथ को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पत्थरबाजी में एक दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं दो संगठनों के विवाद में पथराव के बाद मौके पर पांच थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती के अवसर पर गांव स्थित भैरव बटुक धाम जाने वाले गेट पर कुछ लोगों ने आंबेडकर का झंडा लगाया था। आरोप है कि बाद में कुछ अराजकतत्वों ने झंडे को फाड़कर जला दिया। इसकी सूचना मिलते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो उठे और विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई, जब हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से माहौल गरमा गया और विवाद बढ़ने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इधर, शुक्रवार को फिर दोनों पक्ष आमने- सामने आ गए।